100 दिन विश्वास के

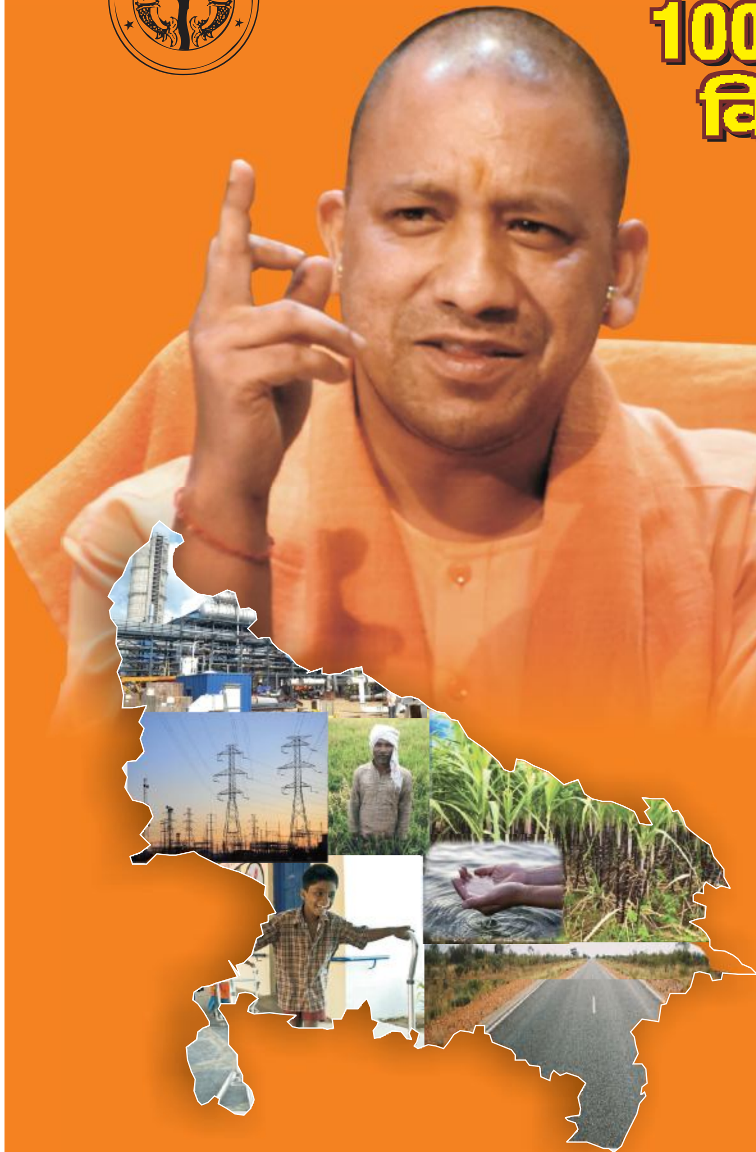

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

लक्ष्य अंत्योदय – प्रण अंत्योदय – पथ अंत्योदय

सबका साथ, सबका विकास

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ.प्र.

100 दिन विश्वास के

विश्वास की बुनियाद पर विकास का अभियान

100 दिन विश्वास के

वर्तमान सरकार ने मात्र 100 दिन में ही अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जिससे आम जन का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। सरकार ने वी.आई.पी. कल्चर को समाप्त करने की साहसिक पहल की है। सरकारी और गैर सरकारी वाहनों से लाल बत्ती के प्रचलन को बंद करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की निर्बाध सप्लाई में विभिन्न जिलों को जो वी.आई.पी. दर्जा मिला हुआ था तथा कुछ चुनिन्दा जिलों को ही 24 घन्टे की विद्युत आपूर्ति मिलती थी उसे समाप्त कर सभी जिलों को एक समान विद्युत आपूर्ति देने का एक साहसिक निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न केवल उनकी कार्यपद्धति की निष्पक्षता प्रमाणित होती है बल्कि उनका यह निर्णय समता व समानता के सिद्धान्त पर भी आधारित है। उनके इस फैसले के बाद प्रदेश में कोई भी जिला वी.आई.पी. नहीं रह गया, सभी एक समान हो गए और सभी को रोस्टर के हिसाब से समान रूप से बिजली की आपूर्ति शुरु कर दी गई। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय को 24 घंटे, ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे, प्रदेश की हर तहसील में और बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे बिजली सप्लाई की पक्की व्यवस्था की गयी है। समान व्यवहार और समान अधिकार के इस सिद्धान्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद ईमानदारी से लागू किया है।

प्रदेश के 86 लाख से अधिक किसानों का 31 मार्च 2016 तक का एक लाख का फसली ऋण माफी का फैसला भी बड़ा और व्यापक प्रभाव वाला है। इससे प्रदेश सरकार पर करीब 36000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आया। इस निर्णय के तहत प्रदेश के 5 एकड़ तक के सभी किसानों के 31 मार्च 2017 तक के बकाया फसली कर्ज माफ करने की व्यवस्था की गयी है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश में वर्षों से अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद करने के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि वर्तमान सरकार किसी प्रकार के अवैध कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद नई खनन नीति को लागू किया। इस नीति के प्रख्यापन के बाद पूरे प्रदेश में खनन से होने वाले राजस्व प्राप्ति के अंश को 1.85 से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इससे आम जन के कल्याणार्थ कार्यों में धन की आवक बढ़ेगी। इस निर्णय के साथ ही अवैध खनन और इसके परिवहन में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी का परिणाम था कि ई–टेण्डरिंग के माध्यम से होने वाले खनन पट्टों में होने वाली राजस्व प्राप्ति पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है।

सरकार की दृढ़ता का एक और उदाहरण है– ई–टेंडरिंग का निर्णय। सभी विभागों में ई– टेंडरिंग के निर्णय से पूरे प्रदेश के ठेकों और सरकारी कार्यों में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोकने की व्यवस्था की गई है। आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए सरकार ने सरकारी डाक्टरों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। सभी जानते हैं कि आबादी के अनुपात में डाक्टरों की कमी है। इस निर्णय से स्वास्थ्य विभाग की कार्यक्षमता और अधिक बढ़ेगी। एक और फैसला सरकार की इस मंशा को उजागर करता है कि वह सरकारी कार्यों के निष्पादन में तेजी लाना चाहती है, इसी के मद्देनजर महापुरुषों के नाम पर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर महापुरुषों के जीवन व उनके आदर्शों से युवा पीढ़ी को अवगत कराने हेतु विद्यालयों में संगोष्ठी आदि आयोजित करने की व्यवस्था की गयी है तथा इस निमित्त 15 सार्वजनिक अवकाशों को निर्बंधित अवकाशों में परिवर्तित कर दिया गया। इसी के साथ ही अपने प्रदेश के बारे में और अधिक जानकारी एवं

जागरूकता लाने के उद्देश्य से 24 जनवरी को 'उत्तर प्रदेश दिवस' मनाने का भी सरकार ने निर्णय लिया गया है।

पिछले कई वर्षों से प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर महिला अपराध बेतहाशा बढ़ रहे थे, इसी के मद्देनजर 'एंटी–रोमियो–स्क्वायड' का गठन प्रदेश के सभी जनपदों में किया गया है। इसके गठन के बाद से प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। स्कूल कालेज, पार्क, मॉल, काफी हाउस, सिनेमाघर, रेलवे और बस स्टेशनों पर होने वाली छेड़खानी अश्लील टिप्पणियां तथा दुर्व्यवहार और यौन अपराधों पर इससे अंकुश लगा है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आपसी सहमति से घूमने वाले जोड़ों को पार्कों में या किसी भी अन्य स्थानों पर उनके घूमने, साथ बैठने आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने इन 100 दिनों में यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को स्थायी रूप से बढ़ावा दिया जाए तथा अपने प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ–साथ देश के अन्य धार्मिक स्थानों पर प्रदेशवासियों की आवाजाही बढ़े। इसके तहत कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 01 लाख रुपए कर दी गयी है। सरकार ने गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण का भी निर्णय लिया है।

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अयोध्या के सरयू घाटों के पुनर्निमाण तथा इनके जीर्णोद्धार के लिए आवश्यकता अनुसार धनराधि अवमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में सरयू घाट पर प्रतिदिन आरती की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी समुचित धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मथुरा वृन्दावन नगर निगम व अयोध्या नगर निगम के गठन का भी निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त निर्णय स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आम जन के विकास, उसकी आकांक्षा और प्रदेश की अस्मिता के सवालों पर कितनी संवेदनशील है। स्पष्ट है कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के स्लोगन के साथ सभी के हित से जुड़े निर्णय ले रही है, जिससे उत्तर प्रदेश का भविष्य संवरेगा। विकास के नए रास्ते खुलेंगे और प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।

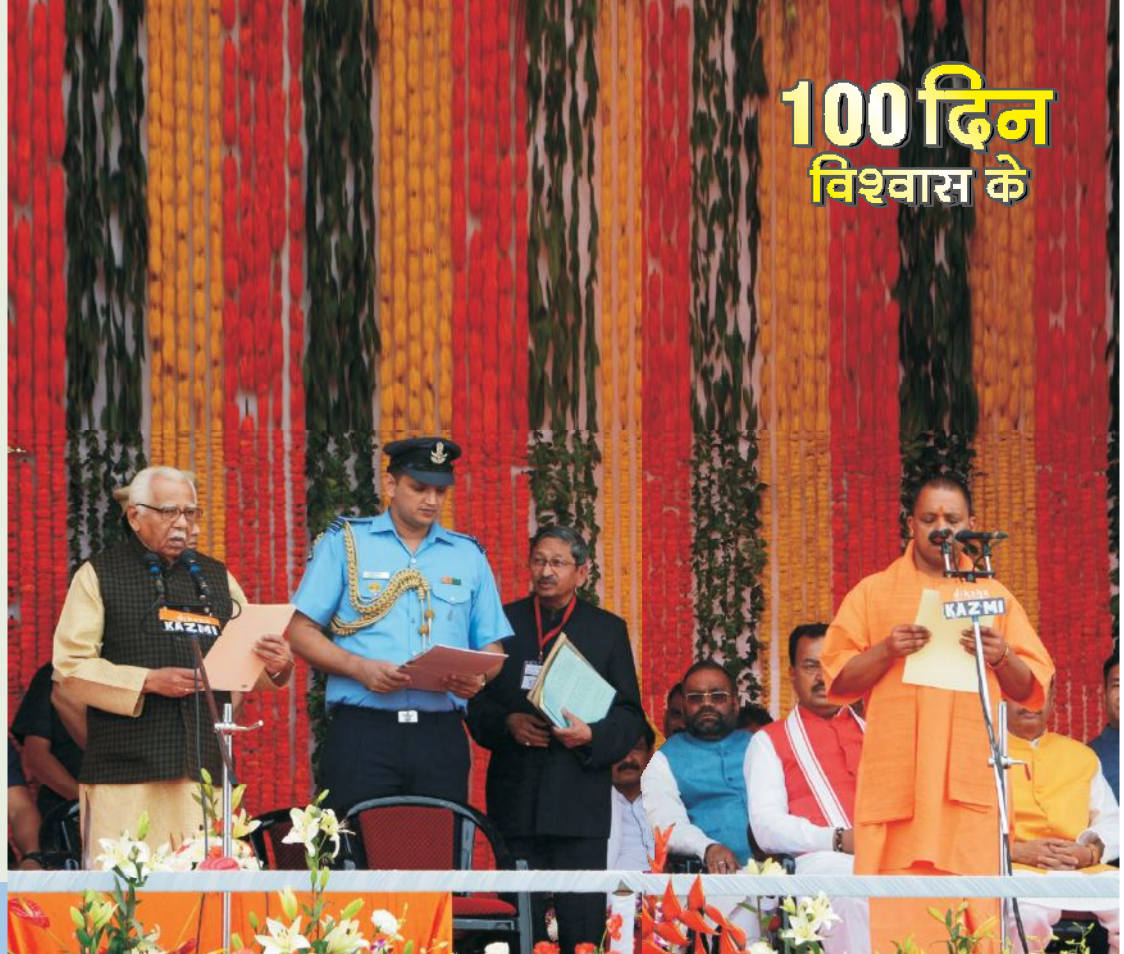

शपथ ग्रहण

दिनांक : 19.03.2017
स्थान : स्मृति उपवन, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने स्मृति उपवन में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर 02 उप मुख्यमंत्रियों – श्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉ0 दिनेश शर्मा एवं 22 कैबिनेट मंत्रियों, 09 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा 13 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी गयी।

पहले 100 घंटे
विश्वास की बुनियाद

इरादों का इज़हार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक में ही स्पष्ट कर दिया कि लोक कल्याण संकल्प–पत्र 2017 में किए गए वादों पर विश्वास करके राज्य की जनता ने इतने बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बनायी है। इसलिए संकल्प–पत्र के सभी बिन्दुओं को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए अधिकारियों से 15 दिनों में अपनी सम्पत्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं जनसामान्य को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि प्रदेश में जवाबदेह, ऊर्जावान एवं प्रगतिशील व्यवस्था देने के लिए सभी संकल्पित हों, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनायें तथा संवेदनशील एवं ईमानदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की जाए। पक्षपात रहित काम करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का सिटीजन चार्टर तैयार किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को राज्य सरकार की सेवाएं निर्धारित समय एवं व्यवस्था के अनुरूप मिल सके। पत्रावलियाँ किसी भी स्तर पर लम्बित नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक दशा में 03 दिनों में उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

हिन्दुस्तानी अकादमी के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं– अवधी, भोजपुरी, ब्रज व बुन्देलखण्डी के संवर्धन व उन्नयन की व्यवस्था।

राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता का अभाव है। इस दिशा में तत्काल कार्य करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि दिसम्बर–2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। उन्होंने सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों की सफाई पर बल दिया।

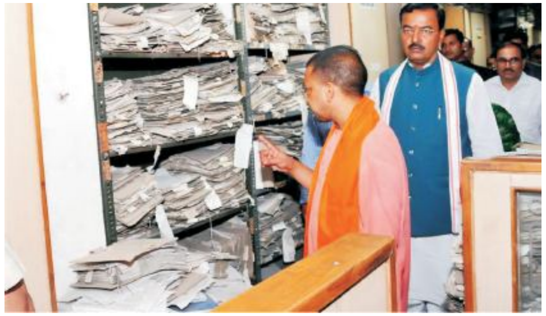

एक ही लक्ष्य
सबका साथ – सबका विकास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के अन्दर 'सबका साथ, सबका विकास' की तर्ज पर विकास का एक नया ढांचा देगी, जिसके तहत समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का एक उत्कृष्ट राज्य होगा, जो भ्रष्टाचार, दंगों, अराजकता व गुण्डागर्दी से मुक्त होगा। विकास का एक ऐसा मॉडल दिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। माताओं और बहनों की सुरक्षा होगी।

योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश की सभी शक्ति पीठों में दर्शनार्थियों के लिए आवश्यक जन सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिये। उन्होंने हर स्तर पर सुरक्षा प्रबन्ध चाक–चौबन्द रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के भी निर्देश दिये। नवरात्रि पर्व के दौरान विन्ध्याचल, देवीपाटन, शाकुम्भरी देवी (सहारनपुर) आदि शक्ति पीठों सहित प्रदेश के समस्त जनपदों के महत्वपूर्ण मन्दिरों में भी साफ–सफाई, पेयजल तथा बिजली आदि की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही,यातायात प्रबन्ध पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई असुविधा न हो।

कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेन्स

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ तस्करी पर अविलम्ब पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने इस अवैध कार्य में लगे अराजक तत्वों की क्षेत्रवार पहचान करने एवं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में संचालित अवैध वूचड़खानों को बंद करने के लिए तत्काल एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न अपराधों के सम्बन्ध में प्रभावी एवं ठोस कार्रवाई की अपेक्षा करते हुए कहा कि पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए। घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस बल को और अधिक चौकस एवं सतर्क रहना होगा। प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय करते हुए इसकी समीक्षा की जाए, विशेष रूप से रात्रि में पुलिस की गश्त पर और अधिक ध्यान दिया जाए, जिससे चोरी एवं डकैती आदि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके।

पहले 100 घंटे
विश्वास की बुनियाद

आमजन की सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का निर्देश देते हुए कहा कि थाने पर फरियाद लेकर आने वाले शिकायतकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ताओं को कागज एवं कलम भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कर थाना प्रभारी द्वारा वैधानिक कार्वाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन यदि जांच के दौरान पता चले कि एफ0आई0आर0 विद्वेष की भावना से गलत दर्ज करायी गयी है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चहुँमुखी विकास एवं इसके प्रति लोगों की धारणा में सुधार के लिए राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जहां राज्य सरकार को पुलिस कार्मिकों से गम्भीरता पूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा है, वहीं इनके लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक गेहूं खरीद केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पेयजल व्यवस्था एवं अन्य जनसुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों को इस आशय के विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवा कर उनकी आर्थिक सम्पन्नता सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है।

100 दिन
विश्वास के

कानून एवं व्यवस्था पर पैनी नज़र

- अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण सृजित कर कानून का राज स्थापित करने के लिये सरकार कृत–संकल्पित।
- महिलाओं/किशोरियों के मन में सुरक्षा का विश्वास जागृत करने हेतु "एन्टी रोमियो स्क्वॉड" का गठन। 8,55,714 व्यक्तियों की जांच, 651 अभियोग पंजीकृत तथा 1367 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं 3,84,921 को चेतावनी।
- पेट्रोल पम्पों में इलेक्ट्रानिक चिप लगाकर बड़े पैमाने पर घटतौली का पूरे देश में पहली बार उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा पर्दाफाश।
- अवैध पशु वध रोकने हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित।

भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत 88,093 अभियोगों में 75,436 अभियुक्त गिरफ्तार, 22,300 अभियुक्त आत्मसमर्पण को मजबूर।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 24 अभियोग पंजीकृत, 24 व्यक्ति निरुद्ध।

लूटी गयी सम्पत्ति रू0 1,72,707,593.00 में से रू0 90,000,016.00 की बरामदगी।

गैंगेस्टर अधियिम के अन्तर्गत पंजीकृत 577 अभियोग में 1,637 अभियुक्त गिरफ्तार।

महिला उत्पीड़न के पंजीकृत 16,152 अभियोगों में 11,922 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 1922 अभियुक्तों का आत्मसमर्पण।

गैगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत रु0 35 करोड़ मूल्य की अवैध सम्पत्ति जब्त।

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों में 3,326 पंजीकृत अभियोगों में 4,620 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 1,148 अभियुक्तों का आत्मसमर्पण।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत 5,067 व्यक्तियों की चालानी रिपोर्ट, 1,597 अभियुक्त निरूद्ध।

10 जून, 2017 से 16 जून, 2017 के बीच 3,413 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 527 अभियुक्त आत्मसमर्पण हेतु बाध्य।

प्रदेश में 392 ईनामी अपराधी गिरफ्तार।

2,999 पेशेवर एवं संगठित अपराधी चिन्हित, 807 अपराधी गिरफ्तार तथा 49 अपराधी आत्मसमर्पण को मजबूर।

पाँच वर्ष से अधिक समय से वांछित अभियुक्तों में से 21 अभियुक्त गिरफ्तार, जिसमें 16 पुरस्कार घोषित अपराधी हैं।

भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाई, भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा 20, सतर्कता अधिष्टान द्वारा 12 तथा जनपदीय पुलिस द्वारा 01 लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

उद्योग से मिलती रोजगार को रफ़्तार

औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर बल। ''मेक इन यू0पी0'' सेल का गठन किया जा रहा है। ''निजी औद्योगिक पार्क'' को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

निवेश को बढ़ावा देने के लिये सुपर मेगा श्रेणी के अन्तर्गत सैमसंग द्वारा 4915 करोड़ रुपये और इंटक्स द्वारा मेगा श्रेणी के अन्तर्गत 372 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर।

वाराणसी के खिलौना क्लस्टर के 20 शिल्पों को पहली बार चेनापट्टम (कर्नाटक) एक्सपोजर विजिट हेतु भेजा गया।

गोरखपुर टेराकोटा क्लस्टर का अध्ययन कराकर उनके संवर्द्धन हेतु कन्सलटेंट द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करा ली गई है।

कैंची क्लस्टर मेरठ जो पिछले एक साल से संचालित नहीं था, उसका संचालन रु0 1.00 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराकर कराया गया।

नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति तथा वस्त्रोद्योग नीति के आलेख तैयार कर उस पर जनमानस के सुझाव प्राप्त। बहुत जल्द ही प्रदेश को आकर्षक नीतियाँ मिलेंगी।

गन्ना किसानों को मीठी सौगात

- गत वर्ष इस अवधि तक रु0 13242.11 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को कराया गया था जबकि इस वर्ष अब तक रु0 22517.52 करोड़ का भुगतान सुनिश्चित कराया गया जो गत वर्ष के सापेक्ष रु0 9275 करोड़ अधिक है।
- निगम क्षेत्र की 02 बंद चीनी मिलों पिपराईच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) में 3500 टी.सी.डी. क्षमता की नयी चीनी मिलों में कोजेन तथा डिस्टलरी प्लाण्ट लगाकर पुर्नसंचालित करने का निर्णय लिया गया।
- निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल के क्षमता विस्तारीकरण एवं कोजेन की स्थापना हेतु शासकीय गारंटी देकर बैंक से रु0 73.96 करोड़ का ऋण स्वीकृत कराया गया जिससे आगामी पेराई सत्र में मिल का विस्तारित क्षमता के साथ समय से संचालन सुनिश्चित कराया जा सके।
- सहकारी क्षेत्र की 23 चीनी मिलों के तकनीकी अपग्रेडेशन हेतु गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में गन्ना शोध एवं चीनी उद्योग से जुडी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के विशेषज्ञों की टीम से मिलों का तकनीकी परीक्षण कराया गया।

स्मार्ट बनेगें उत्तर प्रदेश के शहर

राज्य सरकार के प्रयासों से इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी को भी मिली स्मार्ट सिटी की सौगात।

मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद और रायबरेली को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही सरकार।

लखनऊ, वाराणसी, कानपुर तथा आगरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप।

वाराणसी और मथुरा में हेरिटेज सिटी विकास योजना के तहत संचालित परियोजनाओं पर गुणवत्ता के साथ हो रहा काम।

वाराणसी में 10 परियोजनाओं के लिए 90 करोड़ रुपए और मथुरा में 4 परियोजनाओं के लिए 34 करोड़ रुपए स्वीकृत।

योजना के तहत संचालित परियोजनाओं का कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

किसान को मिले फसल का सही दाम

रबी विपणन वर्ष 2017–18

- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रू0–1625/– प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय।
- रू0 10 प्रति कुन्तल अतिरिक्त भुगतान लोडिंग–अनलोडिंग के लिए 5105 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित।
- 36.99 लाख मी0 टन गेहूँ खरीद की गयी।
- गत वर्ष की कुल खरीद से लगभग 4.5 गुना अधिक।
- 800646 कृषकों को क्रय गेंहू के सापेक्ष रू0 5925.58 करोड़ का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया।

हर खेत को मिले पानी

- सरकार गठन के पश्चात् 30098 निःशुल्क बोरिंग, 563 मध्यम गहरी बोरिंग एवं 258 गहरी बोरिंग पूर्ण की गयी, जिससे 59699 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हो रही है।
- 65 अदद नवीन नलकूपों का ऊर्जीकरण कर जनोपयोगी बनाया गया है, जिससे जनमानस को लाभ मिलेगा।

- भूजल संसाधनों की विषम स्थिति के दृष्टिगत भूगर्भ जल विभाग द्वारा ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' संचालित किये जाने का निर्णय। मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्याग्रस्त कुल 271 विकास खण्डों एवं 22 शहरों का चयन।
- 37 चेकडैम का कार्य पूर्ण, 740 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित। 1 हेक्टेयर से उपर के 178 तालाबों में मिट्टी खुदाई का कार्य पूर्ण किया गया है।

बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर बने विकास का आधार

- लखनऊ से गाजीपुर वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) एक्सप्रेस–वे परियोजना का नाम 'पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे' करने, पूर्व में निष्पादित बिड प्रक्रिया को निरस्त कर नवीन सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुये निर्माणकर्ताओं के चयन की कार्रवाई प्रारम्भ किए जाने तथा 'पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे' को अयोध्या से जोड़ने हेतु एक 'लिंक मार्ग' का निर्माण प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।
- 1,21,000 कि0मी0 गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 80,000 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा 85,000 कि0मी0 गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 72,000 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। शेष पर युद्ध स्तर पर कार्य जारी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 1703 किमी. सड़कों में से 1637.25 किमी. सड़कें गड्ढा मुक्त।
- यातायात को सुगम बनाने हेतु 10 दीर्घ सेतु 05 उपरगामी सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 22 मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण।
- विभाग द्वारा 30 परियोजनाओं/सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 350 किमी0 पूर्ण।
- केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत राज्य को 10,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर सहमति।
- बुन्देलखण्ड के विकास हेतु झांसी से जालौन–उरई–बेला होते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे तक छः लेन राष्ट्रीय मार्ग, जिसकी लम्बाई 320 कि0मी0 एवं आंकलित लागत लगभग रु0 10,000 करोड़ की सहमति भारत सरकार से प्राप्त। झांसी–चित्रकूट–इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, लम्बाई 380 कि0मी0 को चार लेन में परिवर्तित करने की सहमति भारत सरकार से प्राप्त।
- गोवर्धन के विकास हेतु नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण– भारत सरकार से सहमति प्राप्त। राष्ट्रीय मार्ग–2 एवं राष्ट्रीय मार्ग–11 के मध्य चार लेन राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण एवं रेडियल मार्ग सहित गोवर्धन के चारों ओर चार लेन गोवर्धन परिक्रमा मार्ग। प्रस्तावित लम्बाई 99 कि0मी0 आंकलित लागत रु0 4645 करोड़।
- गोरखपुर में दो राष्ट्रीय मार्गों को जोड़कर रू0 1500 करोड़ की लागत से 30 कि0मी0 लम्बे बाइपास के निर्माण की सहमति।
- इलाहाबाद महानगर में रू0 4500 करोड़ की लागत से 76 कि0मी0 लम्बे इनर रिंग रोड के निर्माण की सहमति।
- इलाहाबाद महानगर में गंगा नदी पर रू0 2460 करोड़ की लागत से 4 कि0मी0 लम्बे 6 लेन सेतु के निर्माण की सहमति।
- लखनऊ महानगर में 7 मार्गों पर एलिवेटेड मार्ग के निर्माण की सहमति।
- कानपुर, मेरठ, बरेली एवं मुरादाबाद में रू0 10,900 करोड़ की लागत से बाईपास/रिंग मार्गों के निर्माण की सहमति।

पारदर्शिता से मिलती ''मिनिमम गवर्मेन्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स''

सभी विभागों में ई–टेण्डरिंग व्यवस्था लागू। निविदा प्रणाली में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किये जाने से सामग्री क्रय में न्यूनतम दरें प्राप्त हो सकेंगी।

प्रदेश में अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए खनन प्रक्रिया में सरलीकरण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश खनन नीति–2017 लागू की गयी। इस नीति के अन्तर्गत खनिजों के परिहार की स्वकृति हेतु ई–टेण्डर, ई–नीलामी

निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपखनिज यथा बालू मोरम आदि की अनुपलब्धता के दृष्टिगत प्रदेश में 195 अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र जारी कर एवं उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली–1963 में संशोधन कर अन्य राज्यों से आ रहे उपखनिज के प्रतिबन्ध को समाप्त कर निर्माण कार्य हेतु जनसामान्य के लिए उपखनिज की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

100 दिन विश्वास के

रोशन होगा हर गाँव

प्रदेश में सभी परिवारों को माह अक्टूबर, 2018 तक विद्युत सुलभ कराने के लिए भारत सरकार के साथ 'पावर फार ऑल' का समझौता दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को सम्पन्न।

विद्युत आपूर्ति में आम और खास जिलों का भेदभाव समाप्त। सभी स्थानों पर एक जैसा विद्युत आपूर्ति शिड्यूल लागू। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात्रि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित।

2806 करोड़ रुपये लागत के 23 बड़े विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये गये।

पहली बार किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को लाने–ले जाने एवं 48 घण्टों में प्रतिस्थापित करने हेतु विभागीय व्यवस्था।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 18000 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया।

100 दिन में 6,06,319 पावर कनेक्शन दिये गये।

8000 अतिभारित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि सम्पन्न।

रोशन होगा हर गाँव

- विद्युत उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने और उनके समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रदेशव्यापी हेल्पलाईन '1912' का उच्चीकरण और विस्तारीकरण सम्पन्न।
- ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को भी नि:शुल्क विद्युत संयोजन की सुविधा।
- पहली बार ग्रामीण उपभोक्ताओं को घर बैठकर स्वयं विद्युत बिल सृजित करने एवं भुगतान इण्टरनेट से करने की सुविधा दी गयी। साथ ही विद्युत बिल एवं आपूर्ति सम्बन्धित शिकायत दर्ज कराने हेतु मोबाइल एप द्वारा की सुविधा।
- एम0ओ0यू0 पर आधारित मंहगी बिजली के लिए पूर्व सरकारों द्वारा किये गये करार निरस्त। भविष्य में सभी विद्युत क्रय प्रतिस्पर्धा के आधार पर किए जाने की व्यवस्था लागू की गयी।
- विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए अंतिम अवसर देते हुए सरचार्ज माफी की वनटाईम सैटलमेन्ट योजना तथा विद्युत संयोजनों को नियमित करने के लिए 'सर्वदा' योजना क्रियान्वित। लगभग 20 लाख उपभोक्ता लाभान्वित।
- सौर ऊर्जा आधारित कुल 95 मेगावाट की यूटीलिटी स्केल की विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित की गई।
- पावर फार आल मिशन की पूर्ति के दृष्टिगत निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु नवीन सोलर पॉवर पॉलिसी–2017 का ड्राफ्ट तैयार।
- 14 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों को 18 घण्टे, तहसील व बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे एवं सभी जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का कैबिनेट का फैसला।

10वीं व 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं का नकलविहीन संचालन।

147 मेधावी छात्र–छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मान।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

हर बच्चे को शिक्षा, हर हाथ को काम

कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु अब तक 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से एक–एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

सभी राजकीय महाविद्यालयों में ''परमवीर चक्र'' विजेताओं के चित्र एवं उनका जीवन परिचय विद्यालयों की गैलरियों में लगाने के निर्देश ताकि छात्र–छात्राएं उनकी शौर्य गाथाओं से परिचित हो सके।

उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य कई वर्षों से लम्बित पारस्परिक करार दिनांक 13 जून को हस्ताक्षरित, दोनों राज्यों के 3.5 करोड़ से अधिक यात्रियों का सुलभ होगा आवागमन।

प्रदेश के 3725 गांव, जिनमें अभी तक बस सेवा उपलब्ध नहीं थी उनमें उ0प्र0 परिवहन निगम की बस सेवा शुरू की गई है।

जोड़ेंगे हर गांव शहर

नये मोबाइल एप ''ट्रैक योर बस'' से यात्रियों को बस सेवा का अद्यतन स्थिति, सीट आरक्षण तथा फीडबैक की व्यवस्था उपलब्ध होगी।

54 जनपदों के 63 बस स्टेशनों पर वाई–फाई सुविधा स्थापित। प्रतीक्षारत यात्रियों को सुलभ हुयी ऑनलाइन सेवायें।

परिवहन निगम द्वारा वातानुकूलित हाईएण्ड स्कैनिया एवं वाल्वो सेवा तथा साधारण श्रेणी की वातानुकूलित जनरथ बस सेवा की शुरुआत।

स्वस्थ समाज विकसित प्रदेश

100 दिन विश्वास के

चिकित्सकों की उपलब्धता बनाए रखने की दृष्टि से जनहित में सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।

1000 चिकित्सकों को पदों को वॉक–इन इण्टरव्यू के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।

कार्यरत चिकित्साधिकारियों में से जो चिकित्साधिकारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चाहें, उन्हें विकल्प प्रदान करने तथा चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे चिकित्साधिकारी, जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है, उनकी स्क्रीनिंग करते हुए सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार के सहयोग से 150 एडवान्स लाईफ सपोर्ट (ए0एल0एस0) एम्बुलेन्स सेवाओं का शुभारम्भ। ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से क्रिटिकल मरीजों की हो रही है प्राणरक्षा।

चिकित्सकों के स्थानान्तरण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण बनाए जाने हेतु विभाग में प्रथम बार मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया है।

- प्रदेश के ए0ई0एस0/जे0ई0 से प्रभावित 38 जनपदों में विशेष कैम्प लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया गया। अब तक 88 लाख 62 हजार बच्चों को प्रतिरोधक टीके लगाये गये।
- विभिन्न जनपदो में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कैम्प लगाकर 87 लाख बच्चों का युद्धस्तर पर टीकाकरण कराया गया है।
- गरीब जनता को जैनरिक दवाईयाँ सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए समस्त राजकीय चिकित्सालयों में जैनरिक औषधियों की उपलब्धता हेतु प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

सुलझेगी भूमि विवादों की गुत्थी

पहली बार शासकीय, ग्राम पंचायत व निजी व्यक्तियों की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर दोषियों के विरूद्व विधिक कार्यवाही हेतु एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन तथा एंटी भू–माफिया पोर्टल स्थापना सम्पन्न।

टास्कफोर्स के माध्यम से ग्रामसभा/राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 153808 अतिक्रमणकर्ता चिन्हित, 16505 राजस्व/सिविल वाद दर्ज। 940 प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही।

लगभग 5895 हे0 अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया। 1035 भू–माफियाओं को चिन्हित करते हुए गुण्डा एक्ट के अधीन 42, गैंगस्टर एक्ट के अधीन 17 व अन्य आपराधिक धाराओं की अधीन 371 भू–माफियाओं के विरुद्व कार्यवाही की गयी।

पहली बार राजस्व वादों में नामान्तरण आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया, भूखण्डों के यूनीक कोड का निर्धारण पूर्ण कर लिया गया है। इससे सार्वजनिक उपयोग की भूमि का अवैध अंतरण सम्भव नही हो पायेगा। लगभग 6.50 लाख राजस्व वादों के सापेक्ष 06 लाख वादों में विवादित भूखण्डों का विवरण फीड किया गया।

राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत वाद प्रबंधन प्रणाली में वादग्रस्त भूमि का अंकन किये जाने की व्यवस्था लागू। 94 चकबंदी न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण प्रबंधन प्रणाली विकसित।

मातृ शक्ति को प्रणाम

गुजरात राज्य की भाँति 181–महिला हेल्पलाइन उ0प्र0 के 06 सीटर कॉल सेन्टर 30 सीटर कॉल सेन्टर में विस्तारित। कॉल सेन्टर से प्रदेश के किसी भी स्थान पर महिला के साथ उत्पीड़न होने पर 181 पर डायल करने पर रेस्क्यू टीम/वैन सहायतार्थ तत्काल पहुँचेगी। इस सेवा के माध्यम से किसी महिला को किसी भी क्षेत्र में वांछित सूचना भी ऑनलाइन सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

प्रदेश में गिरते लिंगानुपात की चिन्ताजनक स्थिति के दृष्टिगत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुखबिर योजना की शुरुआत।

महिला सशक्तीकरण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के अवशेष 64 जनपदों में आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना/विस्तार की योजना, प्रथम चरण में अवशेष 64 जनपदों में भी रेस्क्यू वैन उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्ण। फ्लैग ऑफ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.06.2017 को सम्पन्न। उक्त वैन सेवा जी0पी0एस0 सिस्टम से लैस तथा 181–महिला हेल्पलाइन से जुड़ी रहेगी।

100 दिन विश्वास के

दिव्यांगजन : जिनकी क्षमतायें हैं विशेष

दिव्यांगजनों के स्वाभिमान की रक्षा हेतु विभाग का नाम विकलांगजन विकास विभाग से परिवर्तित कर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किया गया।

पहली बार दिव्यांग जन की समस्याओं का निराकरण तथा विभागीय कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु हेल्पलाईन नं0 18001801995 जारी।

दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय।

भारत सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना से आच्छादित दिव्यांगजनों की अनुदान राशि भी 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह।

गाँव से उभरती नये भारत की तस्वीर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी वर्ग के लिए दिए जाने वाले घरों के लक्ष्य में भारी बढ़ोत्तरी। 9,70,108 परिवार होंगे इसी वर्ष लाभान्वित। अब तक 6.37 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया और 5.04 लाख आवास स्वीकृत किये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को मनरेगा के अन्तर्गत मिलेगा जाब–कार्ड एवं 90 दिन का रोजगार।

पूर्व वर्षों के अपूर्ण 15424 इन्दिरा आवास पूर्ण कराये गये।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत 5527 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित 9808 कि0मी0 सड़कों को गड्ढ़ामुक्त किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पिछले कई वर्षों से अधूरी पड़ी 62 सड़कों को पूर्ण कराया गया।

- अयोध्या–फैज़ाबाद एवं वृंदावन–मथुरा को नगर निगम का दर्जा दिया गया।
- झांसी, इलाहाबाद और अलीगढ़ को मिली स्मार्ट सिटी की सौगात।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कराये गये मांग सर्वेक्षण में प्राप्त 317788 आवेदन–पत्रो में से 223816 आवेदन–पत्रों का वैलिडेशन सम्पन्न। 163 नगरों में ई0डब्लू0एस0 के 44335 लाभार्थी आधारित डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रेषित, जिन पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त।

सँवर रहे शहर

- 579 अतिरिक्त वार्डो में डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ। स्वच्छता की स्थिति में गुणात्मक सुधार।
- अयोध्या में सरयू नदी के जीर्ण–शीर्ण घाटों का पुनरोद्धार करने का निर्णय लिया गया। सरयू नदी तट पर गंगा आरती की तर्ज पर प्रत्येक संध्या आरती की व्यवस्था करायी गयी।
- मथुरा–वृन्दावन–बृज परिक्रमा क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास की वृहद् कार्य योजना बनायी गयी है।
- 61 चयनित शहरों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कूड़ा पृथक्करण योजना का अलीगढ़ से शुभारम्भ।

सुधरेगी खजाने की सेहत

जी0एस0टी0 जागरूकता हेतु पूरे प्रदेश में एक हजार से अधिक जी0एस0टी0 कार्यशालाएँ, सेमिनार आयोजित, एक लाख से अधिक व्यापारियों ने किया प्रतिभाग।

बैंक / माईक्रो फाइनेन्स इंस्टिट्यूशन नेटवर्क (एमफिन) के माध्यम से प्रदेश के लगभग 1 लाख व्यक्तियों को ऋण वितरण तथा डिजिटल लिटरेसी कैम्पों का आयोजन किया गया।

जी0एस0टी0 से सम्बन्धित सभी समस्याओं के निस्तारण हेतु वाणिज्य कर के सभी मंडलीय कार्यालयों में जी0एस0टी0 हेल्प डेस्क

बहुप्रतिक्षित माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 दिनांक 19.05.2017 को अधिसूचित।

नीति रीति से नया विज़न

नीति आयोग एवं प्रदेश सरकार का एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन राज्य सरकार की सामाजिक आर्थिक कार्य योजना बनाने हेतु किया गया। उत्तर प्रदेश के चहुँमुखी विकास का खाका तैयार। हर विभाग हेतु एक्शन प्वांइट, मानीटिरेबल आउटकम्स/इन्डीकेटर्स एवं टाइम लाइन्स को सम्मिलित करते हुए एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

आस्था को नमन

कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि रु0 50 हजार से बढ़ाकर रु0 एक लाख प्रति यात्री किया गया।

गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण का निर्णय।

अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण एवं चित्रकूट में परिक्रमा पथ के पुनर्विकास एवं भजन संध्या स्थल के निर्माण का निर्णय।

धर्मार्थ कार्य वेबसाइट का शुभारम्भ सम्पन्न। काशी विश्वनाथ जी की ई–पूजा एवं ऑनलाइन चढ़ावा की सुविधा होगी।

सिन्धु दर्शन का अनुदान वितरण रु0 10 हजार प्रति यात्री किया गया।

बुझेगी बुन्देलखण्ड की प्यास

- बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान की कार्य योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 07 जनपदों में पहले से स्थापित 3,815 हैण्डपम्पों की रीबोरिंग तथा 1,174 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु कुल 40.55 करोड़ रुपए धनराशि की कार्य योजना को मंजूरी।

- बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संचालित पाइप पेय जल योजनाओं को पूरी क्षमता पर क्रियाशील करने हेतु यथा आवश्यक नये नलकूपों के निर्माण, खराब नलकूपों की रीबोरिंग, पम्प एवं पाइप लाइन इत्यादि कार्यों की मरम्मत हेतु 6.48 करोड़ रुपए की कार्य योजना पर सहमति।

यू.पी. के सपनों की उड़ान

जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने की केन्द्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर 'महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल' किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आगरा सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल' किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आओ सीखें आदर्शों से

- निगोशिएबल इंस्ट्रूमेण्ट एक्ट, 1881 से भिन्न 15 कतिपय पर्व आदि एवं महापुरुषों की जन्म तिथियों/पुण्य तिथियों पर घोषित सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

- इन अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में महापुरुषों के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जाएगी।

100 दिन विश्वास के

100 दिन विश्वास के

हमें गर्व है उत्तर प्रदेश पर

24 जनवरी
उत्तर प्रदेश दिवस

24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय। जिन महान विभूतियों ने देश की आजादी में योगदान दिया है, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उन्हें प्रचारित–प्रसारित किया जाएगा।

प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर एवं विविधता को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। नई पीढ़ी को प्रदेश के विकास एवं परिवेश से जोड़ने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राज्य के बाहर अन्य प्रान्तों में रहने वाले प्रवासी प्रदेशवासियों के बीच भी उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे उनकी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के प्रति बढ़ सके।

योग : स्वस्थ जीवन का आधार

तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में मा0 प्रधानमंत्री जी के साथ लगभग 51000 से अधिक लोगों ने बारिश होने के बाद भी उत्सव के माहौल में योगाभ्यास किया। इसके अतिरिक्त लखनऊ के 11 मुख्य पार्कों में भी योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद, तहसील तथा ब्लाक मुख्यालय पर उत्सव के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह आयोजन अपने मूल उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं उनको सहभागी बनाने में सफल रहा।

स्वच्छता बनेगी उत्तर प्रदेश की पहचान

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

- जिलाधिकारी व प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया, नियमित हो रही समीक्षा।
- दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित करने का लक्ष्य।
- पूरे प्रदेश को अक्टूबर, 2018 तक ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित करने का लक्ष्य।
- राज्य के 10 बड़े नगरों में कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को ठोस रूप प्रदान किया जा रहा।
- ठोस अपशिष्ट निस्तारण, पेयजल एवं सीवरेज की व्यवस्था के लिए नई तकनीक पर बल।

नमामि गंगे

- नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत झूंसी, नैनी, फाफामऊ और वृंदावन की कुल 600 करोड़ की योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत।
- प्रयाग अर्द्धकुम्भ–2019 के आयोजन से पूर्व गंगा को स्वच्छ बनाने का काम युद्धस्तर पर जारी।
- गंगा की सहायक नदियों यमुना, गोमती, सरयू, राप्ती और गण्डक को भी निर्मल व स्वच्छ बनाने का संकल्प।
- गंगा किनारे के 1627 गांवों में 4,43,718 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।
- 2 मई 2017 को गंगा नदी के किनारे 25 जनपदों में एवं 595 ग्रामसभाओं में गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस मनाया गया।

वाराणसी का हो रहा है कायाकल्प

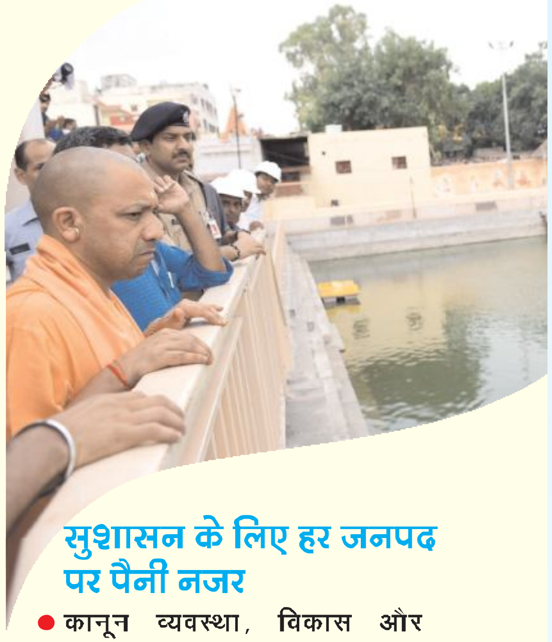

- चौका घाट लहरतारा एवं मंडुआडीह फ्लाईओवरों को निर्धारित समय–सीमा में युद्धस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराए जाने के निर्देश।
- निर्माण से क्षेत्र की पेयजल एवं सीवर लाइनों को नुकसान न पहुंचाने के सख्त निर्देश।
- संकुलधारा तालाब के खुदाई कार्य को तय समय–सीमा में पूर्ण कराने और किनारे लाइटिंग कराने के निर्देश।
- दुर्गाकुंड तालाब के सौंदर्यीकरण व निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर गुणवत्तापूर्वक समय से पूरा करने के निर्देश।
- बीएचयू के सामने घाट की तरफ गंगा नदी पर बनाए जा रहे पुल को 27 जून तक पूरा करने के निर्देश।

सुशासन के लिए हर जनपद पर पैनी नजर

- कानून व्यवस्था, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर विशेष जोर।
- अधिकतर जनसमस्याओं का समाधान ब्लॉक, थाना तथा तहसील स्तर पर करने के निर्देश।
- 100 दिन में मुख्यमंत्री ने खुद की 17 मंडलों की गहन समीक्षा।

खूब पढ़ो खूब बढ़ो

छात्रों को अगले सत्र से एन0सी0ई0आर0टी0 पैटर्न पर शिक्षा मुहैया कराई जाएगी।

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं एवं पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए गंभीर प्रयास।

मिड–डे मील की गुणवत्ता की जांच के लिए 6 सदस्यीय 'मां' नाम से समितियों का गठन।

बच्चों के लिए नया ड्रेस कोड, 1 से 8 तक के सभी बच्चों के आधारकार्ड।

अध्यापकों को स्कूलों में 'लेसन प्लान' के आधार पर ही कक्षाएं संचालित कराने के निर्देश।

डिजिटल इंडिया को रफ्तार देगा यूपी

गरीबों, वंचितों, महिलाओं और जरूरतमन्दों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए 'टेली लॉ सर्विस कॉमन सर्विस सेण्टर्स' की स्थापना।

उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 500 केन्द्रों की स्थापना होगी।

'टेली लॉ सर्विस' के तहत स्थापित किए जा रहे इन 'कॉमन सर्विस सेण्टर्स' में पैरा लीगल वॉलेण्टियर्स की मदद से लोगों को फोन पर मिलेंगी न्यायिक सलाह/सुविधाएं।

6 महीने में राज्य के 100 चिकित्सालयों को ई–हॉस्पिटल योजना से आच्छादित किया जाएगा।

केंद्र की मदद से उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए खोले जाएंगे 8800 सीटों के कई बीपीओ।

झांसी एवं गोरखपुर में 1000–1000 और चित्रकूट में 500 सीटों का बीपीओ खोलने के निर्देश।

बरेली व गाजीपुर में 200–200, कानपुर में 300, लखनऊ में 830, उन्नाव, झांसी एवं इलाहाबाद में 100–100 तथा टीसीएस के माध्यम से वाराणसी में 1000 सीट का बीपीओ बनेगा।

भारत नेट के माध्यम से गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।

अमृत

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

अटल अमृत अभियान

अमृत योजना के अंतर्गत चयनित शहरों में पेयजल एवं सीवरेज आदि के संबंध में रु. 901.84 करोड़ की 57 परियोजनाएं स्वीकृत।

योजना के अंतर्गत 22350 जल संयोजन दिए गए।

इस योजना के अंतर्गत रु. 1851.03 करोड़ की परियोजनाएं तैयार, स्वीकृति की प्रक्रिया में।

9282 अतिरिक्त सामुदायिकध्सार्वजनिक शौचालय सीटों का निर्माण।

100 दिन विश्वास के

मेट्रो की सरपट दौड़

लखनऊ मेट्रो रेल के प्रथम फेज की परियोजना 2019 तक पूरी हो जाएगी।

प्रथम फेज के पहले 8.5 किमी पर मेट्रो को संचालित करने के लिए उठाए जा रहे जरूरी कदम।

मेरठ, आगरा एवं इलाहाबाद मेट्रो एवं रेल के डीपीआर बनाए जा रहे हैं।

झांसी और गोरखपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डीपीआर तैयार।

कानपुर एवं वाराणसी मेट्रो रेल के डीपीआर केन्द्र सरकार को प्रेषित किए जा चुके हैं।